# पत्रिका विज्ञापन

## भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) केन्द्रीय कमेटी

**कोरोना साम्राज्यवादियों द्वारा बनाया गया है, इन साम्राज्यवादियों को नष्ट करने से ही कोरोना का नियंत्रण किया जा सकता है, लॉक डाउन के समय में बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। 10 करोड़ प्रवासी मजदुरों को हर प्रकार की सहायता देना होगा। लॉक डाउन के समय में कहीं–कहीं छुट भी देते हुए इनको अमल करना होगा।**

दिनांक : 13 / 04 / 2020

नोवल कोरोना वायरस (कोविड–19) महामारी से दुनिया के 210 से ज्यादा देशों में विस्तार होने से अभी तक एक लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 16000 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव प्रकरणों की पहचान हुई है। अपने देश में 16000 से ज्यादा लोग इस बीमारी का शिकार हो गये है। सैकडों लोगो कि मृत्यु हो गई है। यह वायरस चाईना के वुहान में पहले अपनी उपस्थिति देकर युरोप, अमेरिका, ब्रिटेन में अपनी मृत्यू श्रृंखला जारी किया है। यह कोरोना वायरस अमेरिका में अपना प्रभाव दिखाने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस वायरस के विस्तार का कारण चाईना होना बताया है, लेकिन चाईना ने इसका खंडन किया। इस संसार में जब तक साम्राज्यवाद रहेगा तब तक युद्ध अनिवार्य रूप से चलता रहेगा। इन युद्धों में विजय हासिल करने के लिए साम्राज्यवादी लोग किसी भी हद तक जा सकते है। वो लोग किसी भी प्रकार का मार्ग अपना सकते है। अमेरिका दूसरे वर्ल्ड वार में परमाणु बम का उपयोग किया गया था। उस समय से यह राष्ट्र मानव के ऊपर युद्ध जारी रखे हुए है। यह पुरे संसार को मालूम है कि वर्तमान में कोरोना जैसे विनाश करने वाला हथियार को वायरस के रूप में पैदा करने का काम इन्हीं साम्राज्यवादियों के वजह से है। वर्तमान में कोरोना ने संसार को पुरा तरह से हिला दिया है।

इस कोरोना वायरस को नियंत्रित करने के लिए पुरे संसार में अलग–अलग शासन द्वारा अलग–अलग कार्रवाही कर रहे है। अपने देश में भी केन्द्र व राज्य शासन के द्वारा कई प्रकार की कार्यवाही की जा रही है, फिर भी यह कार्यवाही बहुत विलंब से किया गया है। अपने देश में केन्द्र शासन द्वारा केरल राज्य में पहला कोरोना पॉजीटीव केश पाया गया जिसके एक महीने के बाद शासन नींद से उठी है। मोदी शासन द्वारा 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का ऐलान किया, उसके बाद 24 मार्च से 14 अप्रैल तक 21 दिन लॉक–डाउन का ऐलान किया गया। नोटबंदी की ही तरह प्रधानमंत्री द्वारा लॉक–डाउन का ऐलान करने से पुरे देश में जनजीवन अस्त–व्यस्त हुई है। मुख्य तौर पर प्रवासी मजदूर, दैनिक मजदूर, निर्धन वर्ग कम से कम 10 करोड लोगों का जीवन अस्त–व्यस्त हो गया है। लॉक–डाउन का ऐलान करते समय प्रधानमंत्री द्वारा इन मजदुरों की सुरक्षा, सरंक्षण के विषय में किसी प्रकार के पैकेज का ऐलान नही किया गया है। डर के मारे यह सभी मजदूर अचानक सड़कों पर आकर

अपने–अपने गॉव जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उस वक्त शासन द्वारा यात्री परिवहन सेवा को बंद कर दिया गया। जिसके परिणाम स्वरूप हजारों की संख्या में मजदूर पैदल अपने गांव की ओर जाने के लिए रोड से पैदल जाने लगे। प्रजा के दयनीय स्थिति का यह एक उदाहरण है। लॉक–डाउन के ऐलान के वक्त इन करोडों मजदूरों की परिस्थितियों का ध्यान रखते हुए उनके लिए भोजन एवं स्वास्थ्य समस्या जैसी मूलभुत सुविधा पर शासन ध्यान देने से यह स्थिति निर्मित नही होती। केन्द्र व राज्य शासन द्वारा कोरोना की दवा नही है, सामाजिक दूरी रखना ही इस वायरस से बचने का एक उपाय है इसके लिए लॉक–डाउन ही सही है। ऐसा जनता को कहा गया। निर्धन व्यक्तियों के परिस्थितियों के मद्दे नजर उनके आर्थिक एवं चिकित्सा सुविधा के विषय में नही सोचा गया। लॉकडाउन का ऐलान करने के 03 दिवस के बाद वित्त मंत्री द्वारा ऐलान किया गया कि पैकेज जी.डी.पी. में 1 प्रतिशत ही है वर्तमान परिस्थिति में गरीबों का भोजन एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्या के निराकरण के लिए कम से कम जीडीपी में 10 प्रतिशत का अलॉटमेंट कि आवश्यकता है। मजदूरों के साथ–साथ, प्रतिदिन कार्य करने वाले छोटे व्यापारी, रिक्शा चालकों, होटल में कार्य करने वाले लोग एवं अन्य कार्मिकों को नौकरी की वजह से खाना मिलता है, इसलिए शासन को इनके मदद के लिए सामने आना चाहिए। अपने देश में वर्तमान में 58 मिलियन टन धान का स्टाक सग्रंहण है। इस स्टाक सग्रंहण में 21 टन स्टाक सग्रंहण को छोडने से, बचा हुआ 37 टन धान को आमलोगों को डिस्ट्रीब्यूट टीम के माध्यम से वितरण किया जा सकता है। सरकार, शासकीय खजानों को नुकसान होगा ऐसा सोचकर, ऐसा कदम नही कर रही है। वर्तमान परिस्थितियों में प्रजा की सुरक्षा ही शासन का मुख्य ध्येय है। आर्थिक स्थिती कैसी भी हो इससे कोई फर्क नही पड़ता। सरकार को गरीबों, किसानों, मजदूरों की आर्थिक व्यवस्था को सुधारना होगा यह वर्तमान परिस्थिति में शासन का प्रथम कर्तव्य है।

कोरोना को नियंत्रित करने के लिए चिकित्सक, नर्स व अन्य स्वास्थ्य कर्मचारी अपने जान की परवाह न करते हुए अपना कर्तव्य निभा रहे है। मुश्किलों का सामना करते हुए अपनी जान कि परवाह न करते हुए कोरोना संक्रमित लोगों को चिकित्सा सेवाएँ दे रहे है। उनको वायरस से सुरक्षित रखने के लिए 7.25 लाख एन–95 मास्क, 60 लाख 03 लेयर वाला मास्क जिसकी एक करोड के आसपास आवश्यकता है। फिर भी इन लोगों को आवश्यक P.P.E. (वायरस सुरक्षा कवच) अपने देश में आवश्यकतानुसार नही है, इस स्थिति के उपर चिकित्सकों के द्वारा आंदोलन किया जा रहा है।

तालिया बजाकर, दीया जलाकर, चिकित्सकों एवं स्वास्थ कर्मचारियों का मनोबल बढाने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा कार्यक्रम किया जा सकता है, लेकिन इन समस्या का निराकरण नही कर सकते।

कोरोना बीमारी में इस्तेमाल होने वाले (एन्टीड्रग) हॉइड्रोक्सी–क्लोरोक्वीन दवाईयों को बाहर भेजना निषेध किया गया है, फिर भी इन दवाईयों को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के कहने पर उनके देश को यह दवाईयॉ भेजी जा रही है, डोनाल्ड ट्रम्प की चेतावनी से मोदी तुरंत इन दवाईयों को अमेरिका भेजा जा रहा है। इस प्रकार अमेरिका की गुलामगिरी

करते हुए देश के स्वास्थय स्थिति के ऊपर ज्यादा ध्यान नही दिया जा रहा है। मोदी सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा लॉक–डाउन एवं सोशल–डिस्टेन्स ही इस समस्या का सही उपाय है, कहकर सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रजा के ऊपर डालकर शासन अपनी जिम्मेदारी से हट रही है।

बीजेपी शासन एवं पार्टी के द्वारा कोरोना फैलने की जिम्मेदारी एक कम्यूनिटी के ऊपर डालकर एक धर्म के ऊपर इसका जिम्मेदारी डाल रही है। मार्च के आखिरी सप्ताह मे दिल्ली के निजामुद्दीन में तबलिकी जमात संस्थान द्वारा आयोजित प्रार्थना कार्यक्रम में जमा हुए लोगों के द्वारा पुरे देश में इस वायरस का विस्तार हुआ। इसका सहारा लेकर बीजेपी एवं आरएसएस उनके ऊपर दुष्प्रचार करते हुए, तबलीकी जमात संस्थान के लोगों पर एक योजनाबद्ध तरीके से वायरस का विस्तार कर रहे है ऐसा कहकर झुठा प्रचार–प्रसार कर रहे है। दरअसल पुरे संसार मे कोरोना का विस्तार होते समय में अपने देश में लाखो लोग विदेश से आ रहे थे, उन्हीं के द्वारा ही अपने देश में इस कोरोना का विस्तार हुआ है। उस समय शासन द्वारा सोये हुई थी और कोई ठोस कदम नही उठाये। सरकार और बीजेपी पार्टी तबलीकी जमात के ऊपर इस गलती को डालने का असली उद्देश्य कोरोना को धर्म का रंग चढ़ाकर मुसलमानों को समाज से दूर कर इन्हें देश से दूर करने का षडयंत्र छुपा हुआ है। यह सच नही है क्या?

कोरोना वायरस, से जनता को सुरक्षा देने के बहाने में शासन द्वारा सभी जनता को स्वयं के निर्बाध में ले गयी। जेल में रहने वाले सभी कैदियो पर भी यह नियम लागू करना होगा फिर भी जेल में उनकी क्षमता से ज्यादा कैदियों को भरा जा रहा है। कैदियों का जीवन संकटमय होता जा रहा है इन लोगों के बीच में कोरोना का असर ज्यादा होगा। जेल में रह रहे बुजूर्गों को कोरोना बीमारी होने की ज्यादा संभावना है। शासन एवं अदालतों द्वारा प्रजा के जीने के हक को सुरक्षा देगें कहकर निर्णय लिया जाता है, अर्बन नक्सलवाद के नाम पर गिरफ्तार किये गये वरवरा राव, 90 प्रतिशत दिव्यांग दिल्ली विश्वविद्यालय प्रोफेसर साईबाबा एवं उनके साथ गिरफ्तार किये गये लोगों को अदालत ने जमानत देने से इंकार किया 60 साल के उपर के लोगो के लिए कोरोना बहुत खतरनाक है। जिसमें गोवा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर वर्नोन गॉन्जाल्विस, सामाजिक कार्यकर्ता गौतम नवल्खा भी है। वर्तमान में कोरोना के खतरे को देखते हुए 5000 प्रमुख व्यक्ति एवं 15 संस्थान द्वारा गिरफ्तार न करने हेतु आवेदन दिया गया किन्तु सुप्रीम कोर्ट में स्टे आवेदन देने पर भी इन लोगों को एक हफ्ते में आत्मसर्मपण करने हेतु पुलिस द्वारा चेतावनी दिया गया। शासन द्वारा चलाया जा रहा ऐसा फॉसिस्ट क्रियाकलाप कोरोना के समय मे असलियत का पता चलता है।

शासन अगले दो हफ्तें के लिए लॉक–डाउन आगे बढाया है। जनता के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए शासन द्वारा बजट कम करने से जनता को तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य का निजीकरण करने से वर्तमान में कोरोना का सामना करने के लिए शासन के पास पर्याप्त सुविधा नही है। स्वास्थ्य व्यवस्था को ज्यादा विकसित करने के बजाय शासन लॉकडाउन के ऊपर निर्भर है। कोरोना के तीव्र गति के विस्तार होने से कोरोना परीक्षण की ज्यादा से ज्यादा आवश्यकता है। यह परीक्षण बार–बार करने से ही समय–समय पर कोरोना

पीड़ित लोगों की पहचान किया जा सकता है। फिर भी शासन के पास कोरोना परीक्षण ज्यादा तादात में करने कि सुविधा उपलब्ध नही है। लॉक–डाउन पर पुलिस व्यवस्था द्वारा अमल कराने का प्रयास किया जा रहा है। इस विषय में जनता को एकजूट करना होगा।

शासन द्वारा भारी मात्रा में कोरोना का परीक्षण कराते हुए, पॉजीटिव लोगों को चिकित्सा की सुविधा देना चाहिए।

देश मे करोडों गरीब, कुली, कार्मिक, किसानों को 5 लाख करोड़ सहायता देना होगा।

डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों आगॅनबाड़ी कार्यकर्ताओं को आवश्यक सहायता भारी मात्रा में देना होगा।

इस समय में प्रजा से आवश्यक सुझाव लेकर शासन द्वारा आवश्यक कार्य करना होगा एवं पत्रकारों को सुरक्षा देना होगा।

कोरोना के लिए कोई धर्म जाति नही है। कोरोना के लिए धर्म का रंग देकर अल्पसंख्यक लोगों को तंग करने बीजेपी एवं आरएसएस को रोकना होगा ।

लॉक–डाउन द्वारा समय में शासन द्वारा खेत में फसल कटाई धान की बिक्री, मांस मछली की बिक्री की तरह ही अन्य व्यापारियों को भी सुविधा देना होगा।

देश में लॉकडाउन को सिर्फ रेड एण्ड हॉट स्पॉट क्षेत्रों की पहचान कर उसी क्षेत्रों में ही लगाना होगा, धनी व सम्पन्न लोग अपनी अय्यासी के लिए इकट्ठा होने वाले जगह को पहचान कर लॉक–डाउन करना होगा।

**हस्ताक्षर**
**अभय**
**अधिकार प्रतिनीधि**
**केन्द्र कम्युनिटी भारतीय**
**कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी)**